



## THE PRINCE OF WALES'S

CORPORATE LEADERS GROUP ON CLIMATE CHANGE  
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE PROGRAMME FOR SUSTAINABILITY LEADERSHIP

### जलवायु परिवर्तन पर कोपेनहेगन की विज्ञप्ति

इस विज्ञप्ति को 500 से भी ज्यादा वैश्विक कंपनियों के उद्यमियों द्वारा जारी किया जा रहा है। यह जलवायु परिवर्तन पर एक महत्वाकांक्षी, मजबूत और न्यायोचित वैश्विक सौदे का आह्वान करती है जो आवश्यक पैमाने पर और अत्यावश्यकता के साथ उस संकट का सामना कर सके जिसका सामना आज दुनिया कर रही है।

इस वर्ष की शुरुआत में, दुनिया की बीस सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ (G20) ने एक साथ मिलकर वैश्विक आर्थिक मंदी पर एक अभूतपूर्व, समन्वित प्रतिक्रिया पर सहमति प्रदान की। लंदन शिखर सम्मेलन में, G20 के लीडरों ने "जो कुछ भी आवश्यक है" उसे करने की शपथ ली जिससे की आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त किया जा सके और आर्थिक प्रणाली का विकास किया जा सके।

दुनिया के लीडरों को अब उसी स्तर के समन्वय को प्रदर्शित करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए संकल्प लेने की जरूरत है। जब तक जलवायु स्थिर नहीं होगा तब तक दीर्घकालीन आर्थिक विकास स्थायी नहीं हो सकता। यह अत्यावश्यक है कि हम इस आर्थिक मंदी से इस प्रकार बाहर निकलें जो कार्बन के कम उत्पादन की नींव डाले और हमारे भविष्य को उच्च कार्बन युक्त पर्यावरण से बचाए।

यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार समुदाय के लिए मुश्किल और चुनौतीपूर्ण समय है और कोपेनहेगन में हुई संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के खराब परिणामों ने अनिश्चितता पैदा करके और कम आत्मविश्वास दिखाकर इसे और मुश्किल और चुनौतीपूर्ण बना दिया है।

इसके विपरीत, यदि एक पर्याप्त महत्वाकांक्षी, प्रभावी और वैश्विक स्तर पर समान समझौते पर सहमति प्रदान की जाती है तो, यह हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था में विकासात्मक परिवर्तन का निर्माण करेगा और यह कंपनियों को निवेश करने के लिए संकेत देगा जिसकी कंपनियां कल्पना करती हैं- यदि वो कम कार्बन उत्पादों, सेवाओं, प्रौद्योगिकी और बुनियादी सुविधाओं में अरबों डॉलर का निवेश करना चाहते हैं।

समझौते का मूल रूप निम्नानुसार होना चाहिए:

- इस समझौते के अंतर्गत 2013 से 2050 (अंतरिम लक्ष्यों के साथ) तक की अवधि के लिए सभी ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन और स्रोतों के न्यूनीकरण के लिए दीर्घकालिक उपायों और वैश्विक उत्सर्जन आवरण का निर्माण किया जाना चाहिए। इन लक्ष्यों को विज्ञान के मार्गदर्शन में किया जाना चाहिए जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वैश्विक ग्रीनहाउस गैस की सांद्रता गंभीर स्तर से कम रहे। इस कथन को व्यक्त करते समय, हम समझते हैं कि पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में वैश्विक औसत तापमान की वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से कम सीमित रखा जाना है और इस उद्देश्य के पीछे एक सर्वसम्मति है जो लगातार बढ़ रही है। इसके लिए यह आवश्यक है कि वैश्विक उत्सर्जन अपनी चरम सीमा पर पहुंचे और फिर अगले दशक में उसमें तेजी से गिरावट शुरू हो। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी/ इंटरगवर्नमेंटल पैनल(आईपीसीसी) की चौथी आकलन रिपोर्ट के अनुसार इस परिदृश्य में भी, 2050 तक 50-85% तक की कमी की आवश्यकता है और उत्सर्जन के चरम स्तर पर पहुंचने में जितनी देर होगी कटौती उतनी ही महंगी होगी। विलंब करने से कोई लाभ नहीं होगा।
- विकसित देशों को उत्सर्जन में कमी करने के लिए जो वैश्विक औसत से कहीं अधिक है उसके लिए तत्काल वचनबद्धता लेनी होगी, जिसे विश्वसनीय रणनीतियों का समर्थन प्राप्त होगा जिससे कि उनकी अर्थव्यवस्थाओं को डि-कार्बोनाइज किया जा सके। विकसित देशों को इस बात का प्रदर्शन करना चाहिए की कम कार्बन विकास प्राप्य और वांछनीय है। उन्हें उन संस्थाओं और उस ढांचे का भी समर्थन करना चाहिए जो विकासशील देशों के लिए आवश्यक वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर सके।
- उत्सर्जन को कम करने से संबंधित अपनी योजना को तैयार करने में विकासशील देशों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए जिसे उनके सामान्य परंतु विभेदित जिम्मेदारियों और क्षमताओं के अनुसार होना चाहिए। उन्नत विकासशील देशों को 2020 तक के लिए उपयुक्त और अर्थव्यवस्था व्यापक प्रतिबद्धताओं के निर्माण की दिशा में निम्न कार्बन विकास योजनाओं को विकसित करना जारी रखना चाहिए। क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और मजबूत वित्तपोषण समाधान के माध्यम से स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को बड़े पैमाने पर तेजी से स्थापित करने के लिए क्षेत्र स्तर पर किए गए कार्य सहायता करेंगे। कम विकसित अर्थव्यवस्थाओं को अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें पर्याप्त वित्त पोषण और सहायता, और विस्तारित सहयोग शामिल है जो उन्हें कम कार्बन अर्थव्यवस्था में शामिल होने और अपनाते में सहायता प्रदान करेगी।

समझौते के मुख्य समर्थन तत्वों में शामिल होना चाहिए:

- **विश्वसनीय माप, रिपोर्टिंग और उत्सर्जन का सत्यापन** जो प्रभावी जलवायु संधि के उद्देश्यों के प्रति प्रगति को मापने के लिए महत्वपूर्ण है।
- **सबसे अधिक कुशल, प्रभावी और साम्यपूर्ण उत्सर्जन कटौती प्रदान करने के लिए मजबूत वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन बाजार** उपलब्ध कराने के लिए उपाय। इसमें राष्ट्रीय या क्षेत्रीय “केप-एंड-ट्रेड” जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ बढ़ती हुई श्रृंखला समाविष्ट होनी चाहिए, जिसमें “केप्स” को नीचे लाकर लक्ष्यों के बराबर किया जाता है जिसे उत्सर्जन कम करने के लिए अपनाया गया है।
- **अतिरिक्त नीतिगत उपाय**, क्योंकि अधिक कार्बन मूल्य अकेले उस स्तर और प्रकृति का परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा जिसकी प्रत्येक अर्थव्यवस्था को आवश्यकता है। ऊर्जा क्षमता में परिवर्तन लाने के लिए, विकास को तेजी से बढ़ावा देने के लिए, निम्न कार्बन प्रौद्योगिकी की व्यापक तैनाती और प्रदर्शन के लिए और साथ ही कम कार्बन उत्पाद और सेवाओं को नए बाजारों में बढ़ावा देने के लिए उपायों की आवश्यकता है। इन उपायों में महत्वाकांक्षी प्रदर्शन और दक्षता मानक, लोगों की खरीद के प्रति प्रतिबद्धता, और विकास के लिए प्रोत्साहन भी शामिल है। मजबूत बौद्धिक संपदा संरक्षण और साथ ही अन्य सक्रिय नीतियां भी प्रमुख हैं।
- **विकासशील देशों के लिए** ढांचा जिससे कि वो मजबूत निधीकरण समाधानों के माध्यम से बड़े पैमाने पर स्वच्छ प्रौद्योगिकियों की तैनाती में तेजी ला सकें, तथा उत्सर्जन कम करने की प्रतिबद्धताओं को स्वीकार कर सकें। स्वच्छ विकास व्यवस्था (सीडीएम) को संशोधित किया जाना चाहिए जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वो विकासशील देशों को वित्तीय सहायता और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को उस पैमाने पर प्रदान कर सकें जिसकी उनको आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए, सीडीएम को परियोजना आधारित व्यवस्था से थोक व्यवस्था की ओर जाना होगा जो अतिरिक्त उत्सर्जन में कमी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संधारणीयता मानदंड के अनुसार एक पारदर्शी, मजबूत और विश्वसनीय तरीके से कार्बन वृद्धि को कम करने में सहायता करे।
- उन सबसे गरीब देशों और लोगों के लिए जो खासतौर से **जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से प्रभावित हुए हैं**, जबकि वो इस समस्या के लिए कम से कम जिम्मेदार हैं उनकी सहायता के लिए एक अनुकूलन रूपरेखा और वित्तपोषण व्यवस्था। अनुकूलन वित्तपोषण को स्थिर, पूर्वानुमेय, स्थायी और पर्याप्त होने की जरूरत है। सरकार को अपने जलवायु संबंधी जोखिमों का विश्लेषण करना चाहिए और अपने मूल्यांकनों को संग्रहित करना चाहिए।
- **विकासशील देशों में वनों की कटाई और वनों की कमी से होने वाले उत्सर्जन को कम करने की व्यवस्था (REDD)**, जिसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विकासशील देश जो वनों की कटाई और वनों की कमी के कारण होने वाले उत्सर्जन को कम करते हैं उनको पर्याप्त, पूर्वानुमेय, परिणाम आधारित, और दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। उष्णकटिबंधीय वन राष्ट्रों को पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध कराने के लिए एक तत्काल अंतरिम आपातकालीन पैकेज की भी आवश्यकता है जिससे कि वो REDD के पूर्ण कार्यान्वयन से पहले ही अल्पावधि में वनों की कटाई को रोक सकें और वैकल्पिक आर्थिक विकास को अपना सकें।
- **अंतरराष्ट्रीय विमानन और नौवहन** से होने वाले उत्सर्जन के लिए एक व्यापक वैश्विक दृष्टिकोण, और कार्बन प्रग्रहण और भंडारण को व्यापारिक बनाने के लिए एक स्पष्ट रणनीति, जिससे की इसे व्यापक रूप से तैनात किया जा सके।

समझौते की शक्ति का निर्णय उसकी इस क्षमता के आधार पर किया जाएगा कि वो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, संयुक्त राष्ट्र की प्रक्रिया के अंतर्गत और उसके बाहर मौलिक कार्यों का चालन कर सकता है या नहीं, परंतु इनको उन सिद्धांतों के अनुसार होना चाहिए जिन पर कोपेनहेगन में सहमति प्रदान की गई थी।

एक मजबूत, प्रभावी और समान अंतरराष्ट्रीय जलवायु ढांचा घरेलू नीतिगत हस्तक्षेप, द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सौदों को प्रोत्साहित करेगा जो मध्यम और लंबी अवधि के लिए उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अतिआवश्यक हैं और साथ ही यह निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था के निर्माण में तेजी प्रदान करेगा। यह व्यापार की संभावनाओं को खोल देगा वो करने के लिए जो यह सबसे बेहतर करता है: फायदे के लिए निवेश करने के लिए, कुछ नया करने के लिए, और दुनिया भर के अरबों उपभोक्ताओं के लिए सस्ते निम्न-कार्बन उत्पादों और सेवाओं को बनाने के लिए। ढांचा जितना अधिक महत्वाकांक्षी होगा व्यापार का उतना अधिक प्रसार होगा।

जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान है- अनेक आवश्यक तकनीकें आज उपलब्ध हैं जबकि अन्य विकसित की जा सकती हैं। आवश्यक नीतियां स्पष्ट हैं, और आज की आर्थिक स्थिति में भी अवस्थांतर प्रबन्धनीय है। एक चीज जो हमारे पास नहीं है वो है समय। विलंब कोई विकल्प नहीं है।

एक पहल जिसका विकास



द्वारा किया गया है